18.02 hrs.

MOTION RE. ATROCITIES ON HARIJANS—*Contd.*

MR CHAIRMAN We will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Ram Vilas Paswan on the 4th April, 1978, namely·—

> "That this House expresses its concern at the atrocities being committed on Harijans in Bihar, U P, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and other parts of the country"

along with the amendments moved thereon

SHRI B SHANKARANAND (Chikkodi) Mr Chairman, I would like to make a submission before the discussion is started Now, out of six hours time allotted to this subject, the time left for Janata Party is only 28 minutes and for my party i e, Congress—I, it is 24 minutes and for the Congress Party it is 19 minutes So, the time may be allowed accordingly to the respective speakers I have submitted only three names from my party and I request that eight minutes may be given to each Member of my party

MR CHAIRMAN Let us see

SHRI C M STEPHEN (Idukki)· There is no question of "let us see"

श्री युवराज (कटिहार) सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है पांच माननीय सदस्यों ने इस मोशन पर संशोधन प्रस्तुत किये हैं। उन में से श्री मण्डल कल अपने संशोधन के पक्ष में तर्क पेश कर चुके हैं। बाकी चार सदस्य बचे हैं। मेरा प्रार्थना है कि जिन सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, आज ही सूची से उन्हें प्राथमिकता दी जाये।

श्री आर० एन० राकेश (चायल) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते थे, उन्हें भी अभी तक समय नहीं मिल पाया है। उन्हें इस बारे में महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं। मेरा अनुरोध है कि उन्हें वरीयता दी जाये।

श्री शिवनरायण सरसूनिया (करोल बाग)। सभापति महोदय, हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में पिछले दो दिनों में भरपूर बहस हो चुकी है। इस सम्बन्ध में श्री रामधन जी द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। हमारे अन्य साथियों ने भी दिनों-दिन होने वाली बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया है, जिन को पुन आप के सामने रख कर मैं इस सदन का समय नहीं लेना चाहता हू।

18 04 hrs

[DR SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

संविधान में हमें जो आरक्षण दिया गया है, उस के सम्बन्ध में संविधान में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक कमीशन बनाया जायेगा, जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के लिए व्यवस्थायें करेगा। परन्तु इस कमीशन की आज तक की सारी रिपोर्टों और सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। इस के अलावा डिपुटी कमिश्नरों के दफ्तर बन्द कर दिये गये हैं। यह कहना चाहिए कि इस कमीशन के पर काट दिये गये हैं। बशक यह समूचा पाप पिछली सरकार ने किया। लेकिन हम ने सब को सुधारने, उस को आगे बढ़ाने और वह कमीशन कुछ एफेक्टिव हो सके, उस के लिए अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किए गए। लोगों के ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं घटती हैं उस के साथ साथ गृह मंत्रालय में हमारे संरक्षण के लिए जो आरक्षण के और अस्पृश्यता निवारण के लिए

जो कानून था उस को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। सरकारी नौकरियों में हमारी स्थिति अभी तक बिलकुल नगण्य सी चली आ रही है क्योंकि यह सरकार चाहे किसी को भी रही है लेकिन उस ने ईमानदारी से उन का पालन नहीं किया। उस के बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। सब से पहले एक तो यह उदाहरण है कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने जब कम्यूनल एवार्ड के आधार पर मुसलमानों को सन् 1939 में रिजर्वेशन दिया था तो केवल सात साल के अंदर जितना रिजर्वेशन उन को दिया गया था, शत प्रतिशत उसे पूरा कर दिया गया लेकिन इधर अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की स्थिति यह है कि 31 वर्ष पूरे हो गए, टार्गेट प्राप्त करना तो दूर रहा, उस का आधा या चौथाई भी अभी तक नहीं हुआ। यों यह जो संरक्षण है यह केवल सरकारी नौकरियों में है, लेकिन उस के साथ साथ अर्द्ध सरकारी जितनी अंडरटेकिंग्स है उन के बारे में मैंने अभी इसी सदन में प्रश्न किया था कि हर मिनिस्ट्री के नीचे जितनी अंडरटेकिंग्स आती हैं उन में प्रत्येक में अनुसूचित जाति के लोगों की सेवाओं में किस तरह की स्थिति है लेकिन मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख है कि हर अंडरटेकिंग से जवाब यह आया है कि अभी तक इन्फार्मेशन कलेक्ट की जा रही है। जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से प्रावधान है कि एक चालीस प्वाइंट रोस्टर बनेगा और उस के हिसाब से सीटें एलाट होंगी, उसी तरह से उन को सब जगह संरक्षण दिया जायगा और उस की पूर्ति की जायगी, यदि वह नियम आज तक वहां पर लागू किए गए होते तो आज यह स्थिति न होती कि हमारे सामने उस का चित्र न आए। सरकार की ओर से रोज नारे दिये जाते हैं, चिन्ताएं व्यक्त की जातीं हैं, नेता भाषण देते हैं, लेकिन उस के पीछे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वह टस से मस नहीं होती, वह उन नियमों को ऐसे तोड़ मोड़ देती है कि जिस के कारण लोग वहां आ नहीं पाते हैं। अभी अभी अंडर सेक्रेटरियों को सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी बनाने की लिस्ट सरकार की तरफ से आया हुई। उन के अंदर एक भी अनुसूचित जाती के सदस्य को नहीं लिया गया है। हमारे अनुसूचित जाति के सदस्य जितने भी आइ० ए०एस० में हैं उन में से बहुत से ऐसे हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से वे बिलकुल सीनियर थे और उसी तरह से उन का आउट-स्टैंडिंग रेकार्ड था लेकिन उस के बाद भी उन को इग्नोर कर दिया गया। आज भी अभी मोटरोलाजिकल टिपार्टमेंट में एक शेडयूल्ड कास्ट आफिसर को जो साल भर पहले प्रोमोशन दिया हुआ था उस को इसलिए रिवर्ट किया जा रहा है कि दूसरी जगह किसी दूसरे को प्रोमोशन दे दिया। हमारे साथ इस तरह से द्वितीय नागरिक वाला व्यवहार सदा सदा से चला आ रहा है : हमारे लिए जो कुछ भी संरक्षण या दूसरी बातें रखी गई है गृह मंत्रालय उस को पूरा नहीं कर पाया। मैंने तीन मंत्रालयों के बारे में जानकारी हासिल की, वहां पर जो प्रशिक्षित लोग हमारे पास मौजूद है, उन के पत्रों के बारे में, उन के जो टैस्ट हुए है उन के बारे में, उन के जो इंटरव्यू हुए है उन सब के बारे में उन की स्थिति अच्छी होते हुए भी उन को अप्वाइंटमेंट नहीं दिया गया और यह कह दिया गया कि नहीं, वे सक्षम नहीं थे जब कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी आदेश है कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के प्रत्याशी यदि किसी विशेष प्रशिक्षण में प्रशिक्षित नहीं मिलते हैं और वे मिनिमम ऐकेडेमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त हैं तो उन को ले कर वह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए लेकिन ये जितनी जागीरें, अंडरटेकिंग्स बनी है इन सब जागीरों में जो उन के डयरेक्टर और परसोनल डायरेक्टर हैं वे गृह मंत्रालय के किसी भी नियम का पालन नहीं करते। वे उस के ऊपर ध्यान नहीं देते, स्वतंत्रता से चलते हैं और उस के कारण अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों पर कुठाराघात

[श्री शिव नारायण सरसूनिया]

हो रहा है। इस प्रकार से इस ओर जो ध्यान देना चाहिए वह अभी तक नही दिया जा सका।

हम जब मंत्रियो से बात करते हैं तो हमें कई बार इस तरह की चीजें मिलती हैं जिनके ऊपर हमे दुख होता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी के पास एक समस्या के लिए गया था। मैने जाकर प्रार्थना की कि मैं मिलना चाहता हू, आप मुझे टाइम दीजिए। पहले मिलने के लिए इनकार कर दिया फिर अकेले मुझ से मिले तो मिलने पर जो उनके रिमार्क्स थे वह आज भी मेरे दिलो दिमाग पर बोझ बने हुए हैं। उनके बारे में आज तक कही कोई उत्तर नही है। उन्होंने कहा तुम्हारा लिस्ट में नाम है, तुम कहो, क्या कहना चाहते हो। उसके बाद जब मेरी बात सुनी तो कहते हैं नहीं, यह तुमने कामपिरेसी चला रखी है, तुमने लहर चला रखी है, मेरे खिलाफ आन्दोलन बना रखा है। और भी दो तीन एम०पीज० के नाम लिए, कि इन सब ने मेरे खिलाफ केस रचा रखा है। इसी तरह के आप ला एड आर्डर की बात करते हैं, लोग तो रोज मरते रहते हैं, सृष्टि के आरम्भ से। क्या बन्द हुआ है ? और न आगे बन्द होगा। जब इस तरह का जवाब हमें मिलेगा तो किस तरह से हमें विश्वास होगा कि हमारा सरक्षण किया जायेगा। उसके बाद लिस्ट में जो बात कही वह भी मैं आपको बताना चाहता हू। उन्होंने कहा अच्छा, यह तो सब कुछ होता रहेगा, इनकी बात क्या करोगे, तुम अपनी बात कर लो। तुम्हारे ऊपर आफत आने वाली है, अपने घर को बचाओ। हम यहां पर लोकसभा में चुनकर आये हैं, हमें मीसा से डर नहीं लगा, हम जिन्दगी की परवाह नहीं करते हैं, किसी से बिक कर नहीं आये लेकिन होम मंत्रालय के मंत्री महोदय हमें इस तरह से थ्रेटन करें जबकि हम इस बात के लिए उनके पास जायें कि हमारे इलाके की ला एड आर्डर की स्थिति खराब है तब वे कहें कि तुम्हारे घर पर आग लगी हुई है। तुम्हारे ऊपर आफत आने वाली है, तुम अपनी आग बुझाओ। 25 तारीख को मेरे साथ यह घटना घटी, मैने वरिष्ठ अधिकारियो को लिखा लेकिन किसी ने आज तक मुझे संतोष नही दिया। कम से कम यही कह देते कि नही, यह कोई बात नही है, यह एक के साथ नही, बहुत से हरिजनो के साथ यह बात हुई है। मै किसी एक व्यक्ति के विरोध मे नही हू। हमारे साथियो ने जो कुछ बाते रखी है उनके ऊपर कुछ लोगो का मत लगता है कि हम जान बूझ कर अलग जा रहे है लेकिन हम जनता पार्टी के है, एक नौका में हम बैठे हैं परन्तु हमारे साथ जो व्यवहार होता है, जो घटनाये होती है वह हमारे अन्दर जो बेदनायें पैदा करती है, रोज हमारे ऊपर अत्याचार होते है, कत्ल होते है उसको सुनने के लिए काई तैयार नही और इस तरह की दलीलें दी जाती है जिनका कोई तुक नही। आखिर इन बातो को सुनकर किसका हृदय खराब नही होगा, कौन दु खी नही होगा ? हम इस बात को नही सोचते कि यह किसी पार्टी का मामला है बल्कि यह राष्ट्रीय मसला है, नेशनल मसला है।

सबसे पहले लैण्ड रिफार्म का नारा दिया गया। जमीदारो से जमीन छीन ली गई लेकिन हमे नही दी गई। हमारे नाम पर उनसे जमीन छीनी गई लेकिन हम लोग आज भी जमीन के बगैर है। जिनको जमीन दी गई वे काश्त नही कर सकते। उन्होंने जमीन को अच्छा बना लिया तो उसके बाद उनसे जमीन छीनी जा रही है। यह स्थिति हर जगह है। दिल्ली प्रदेश मे मैं था तो कझोला गांव में जिनको जमीन दी थीं वहां पर अभी महीने महीने भर पुलिस इसलिए बैठी कि वे अपनी काश्त कर सकें। जब दिल्ली की यह स्थिति है तो फिर देश के गांवों में क्या स्थिति होगी ? अभी 8-10 दिन पहले मेरे क्षेत्र में एक गांव की बात है, गांव के लोगों

ने एक महिला के साथ जबर्दस्ती करनी चाही, उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखानी चाही तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज यह कहा जा रहा कि रिपोर्टें ज्यादा लिखी जा रही है, इस लिये बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है, आधी से ज्यादा रिपोर्टें तो लिखी ही नहीं जाती। बहुत ज्यादा घटनायें हो रही है, पहले भी होती थी, लेकिन क्या यह इसी तरह से होता रहेगा? क्या हम को द्वितीय नागरिक बन कर रहना होगा? इस के लिये कोई कारगर कदम उठाना होगा। जनता ने करवट बदली है, पुरानी सरकार को बदल कर नई सरकार आई है—इस परिवर्तन में हरिजनों, बैकवर्ड क्लासेज के लोगों और तमाम गरीबों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने भी इस परिवर्तन में बहुत बड़ा भाग लिया है, इसलिये उन को इन्कार नहीं किया जा सकता है। उनकी स्थिति को नहीं सुधारा गया, उनकी जमीन का जो झगड़ा चल रहा है, यदि उस को हल नहीं किया गया, तो यह झगड़ा और ज्यादा बढ़ेगा।

हमारे भाई रामधन जी ने कहा कि हम इस मामले को यू०एन०ओ० में ले जायेंगे। हमारे बहुत से मित्र कहते हैं—यू०एन०ओ० में ले जाने से क्या हल निकलने वाला है, क्या वहां ले जा कर हम यह कहेंगे कि हमें बचाओ, हम मारे जा रहे है, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। मैं उन को बतलाना चाहता हूं—यदि हमारे साथ इसी तरह का व्यवहार होता रहा, तो हम मांग करेंगे कि हमारा स्थायी स्थान होना चाहिये, हमारी जगह होनी चाहिये, हमारी जमीन होनी चाहिए, जिस के ऊपर हम इज्जत से रह सकें। बाबा साहब अम्बेदकर ने जिस समय आन्दोलन शुरू किया था और कहा था कि हमारा इलैक्टोरेट अलग होना चाहिये, अगर उस समय उन की मांग को मान लिया गया होता, तो यह समस्या आज हल हो गई होती। अगर उस समय महात्मा गांधी ने आमरण-अनशन कर के उन से इस तरह का आन्दोलन न करने का वचन ले लिया था, जिस की वजह से यह समस्या आज भी उसी तरह से बनी हुई है।

सभापति महोदय, इसी दिल्ली में जब दोनों प्रावधान फेल हो गये, गृह मंत्रालय हमें सुरक्षा नहीं दे पाया और राष्ट्रपति द्वारा बनाया हुआ इदारा भी फेल हो गया, वह भी हमें संरक्षण न दे सका, हमारे लिये प्रावधान नहीं बना सका, तो फिर हरिजनों ने पिछले सोमवार से भूख-हड़ताल शुरू की। 101 हरिजन रोज वोट-क्लब पर 24 घंटे भूख हड़ताल करते रहे—मैं पूछता हूं क्या किसी ने वहां जा कर उन के दुख-दर्द को पूछा? यहां पर जो पहली सरकार थी—उस के कारनामों का हम जानते है। जब कहीं बाढ़ आई तो उस ने झूठा प्रचार किया कि हरिजनों के खेत डूब गये जब कि उन को कुछ भी नहीं दिया गया था, लेकिन आज तो हमारे आंसू तक भी पोंछने के लिये कोई तैयार नहीं है।

इस लिये मैं कहना चाहता हूं—कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये, इस तरह से शुरुआत होनी चाहिये, जिस से हम को लगे कि वास्तव में हमारी सुनवाई हो रही है। आज जो लोग यहां अपने विचारों को व्यक्त कर रहे है, इसलिये नहीं कर रहे हैं कि हम केवल अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि इस लिये कर रहे है कि हमारे पीछे जो समाज बैठा हुआ है, जो रोता है, बिलखता है और कहता है कि तुम्हारे यहां बैठे होने के बावजूद भी हमारे साथ यह व्यवहार हो रहा है, हमारा यह हाल हो रहा है। इस समाज को बरगला कर पिछली हुकूमत ने 30–31 साल तक यहां हुकूमत की, लेकिन अब यदि उसी समाज के साथ ठीक तरह से, सन्तुलित रूप से व्यवहार नहीं किया गया, उस की परवाह नहीं की गई, तो इस के परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसी लिये, सभापति महोदय, हम ने एक नई मांग की है, एक नया विकल्प दिया है कि हमारा

[श्री शिवनारायण सरसूनिया]

एक अलग मंत्रालय बनाया जाय, जिस तरह से आप का रिहैबिलिटेशन मंत्रालय बना हुआ है। पाकिस्तान से उजड़ कर दो करोड़ लोग यहां आये, उन के लिये अलग से व्यवस्था की गई और उस व्यवस्था के कारण वे 10-15 साल में आबाद हो गये, हम जो हजारों सालों से उजड़े हुए हैं, क्या हमारे लिये उस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती? अगर इस तरह की सशक्त व्यवस्था हिन्दुस्तान में कायम कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि जो बार-बार संरक्षण का सवाल पैदा होता है, वह सवाल पैदा ही न हो। और हमेशा के लिये हल हो जाय।

आज हमारे जितने भी आफिसर्ज लगे हुए हैं, वे सब परेशान हैं। क्योंकि उन के खिलाफ इस तरह के संघ बन गये हैं —जो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, एन्टी-रिजर्वेशन के नारे लग रहे हैं। आज रिजर्वेशन के प्रति इतनी गलत बात पैदा कर दी गई है, ऐसी भावनायें पैदा कर दी गई हैं—जब कि हमें केवल 15 प्रतिशत दिया जा रहा है और 85 प्रतिशत उन्होंने अपने लिये रिजर्वेशन किया हुआ—लेकिन उस के बाद भी हमारे ऊपर आक्षेप लगाये जाते हैं, छींटे कसे जाते हैं कि यह सरकार तो हमारे लिये है।

जो संकल्प यहां रखा गया है, उस का समर्थन करते हुए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस तरह की कोई न कोई मशीनरी कायम हो जिससे हमारे ऊपर जो जुल्म किये जाते हैं, उन को रोका जा सके। हमारे साथ जो व्यवहार होता है उस में स्वच्छता आनी चाहिये, दोषियों को दण्ड दिया जाना चाहिये, जिस से हमारे समाज को यह विश्वास हो सके कि यह सरकार अब हमारी है और हमारे लिये कुछ करने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN (Satara): I am grateful to you for giving me time now when I can get the Prime Minister's attention when I am speaking. He is happily present here. May be I will not be present when he replies, I am saying that in advance.

I am very glad indeed that the House had decided to give some extra time to consider this motion before the House, in which the House proposes to express its concern. I think this is the minimum that we can do about this problem. It is in this softer way the question is on the agenda of the House today. But I must remind the House and the Prime Minister particularly that this question in this peculiarly difficult form has been on the agenda of our national life for the last one year. This is not something which has happened overnight in the last few weeks.

I know somebody can say that the question of the Harijans, the scheduled castes and scheduled tribes, is not a question of recent origin, it stretches back to so many years, to the centuries. So, how can you say it is only for the last one year?

When I am saying one year, I refer to the particular form, the extreme form of the atrocities. It was, really speaking, a warning to the nation, that something very serious was happening, that somebody must sit up very seriously and apply his mind to it. It was in this acute form that this question was before the country.

When we were trying to raise this question here in the House about what happened in Belchi, in Meerut and other districts...

AN HON. MEMBER: In Maharashtra.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: In Maharashtra. If it has happened in Maharashtra, I can say I am ashamed of it, there is nothing to be proud about, there is nothing to explain away. I am equally ashamed of it if it is happening in Maharashtra.

But my main point is that when we were trying to invite the attention of the Government and trying to have some sort of constructive dialogue with Government, I must say that out of despair I had to give up this effort with the Prime Minister. I would remind him about my correspondence with him on this question.

18.23 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

When I wrote to the Prime Minister, sending along with my letter a report of some of the members of the party who visited, some of the States, not only Belchi—they had gone to Bihar, and then to Gujarat and some other places—I was told by the Prime Minister that this was politically motivated. Therefore, I had to give up the correspondence out of sheer despair.

With all my respect to him, my main objective at that time was to establish some sort of constructive communication and dialogue, because this is not a question of one party, of the State Government or the Central Government, this is not a question where you can say that it falls in the State List or the Central List or the Concurrent List. This is a question which lies on the national conscience, therefore, the nation has to take it in the correct spirit and face the question I must say that all these things, all these issues or incidents were happening in different States, all the States I would say if that satisfies somebody, but the question is not where it happened, but that they were happening, and one has to go into the reasons for it.

From the details that some of the members of the party then gave me, it had some special provocation this year, in the last few years if you like. Some new rights were given to the Harijans, some lands were given, bonded labour was sought to be removed. It is this which was, really speaking, giving them some human rights for the first time in practice. It happened because people who were not pleased with these things were taking a sort of anti-social attitude and making an organised effort to attack the Harijans and the result was the atrocities. Therefore, it has social and historical significance. If you merely rule it away as a problem of law and order, it will be a great mistake. We have then not understood the problem at all. The problem of Scheduled Castes, the problem of Scheduled Tribes and minorities is a problem which requires awakening of social conscience of the nation. For that matter, all the parties together have to have some sort of a constructive programme. But the Government will have to take a lead in this matter and take a special responsibility. Every time we come here and some Members raise this question, it is found that it is merely explained away in a routine manner. That hurts more. We are told that Harijans are 15 per cent and the atrocities are only 1 per cent This sort of an explanation of happenings in the country in a statistical way is adding insult to injury. Therefore, I do not merely take this opportunity and criticise the Government but I am again making an apeal to the Prime Minister because he himself is a well known leader who has his own idea about it; I know that he has also done something in this matter in a constructive way, not that I need to speak about it But I certainly say that we need to emphasise this particular aspect because it has assumed special significance now.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): What is your constructive suggestion?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: If you sit along the table, certainly we can talk about it. At least economic rights and social privileges that they are getting today, some people are getting jeolous about it and are trying to deny those things. Certain elements in society in an organised fashion try to do it and if these elements get protection from the Government indirectly by connivance, by negligence, by positive support then what happens? This is the main question. As I told you, specific instances were

[Shri Yashwantrao Chavan]

brought to notice that certain lands were given to the people in the last two, three years, and by forcefully attacking these people, they were dispossessed of the lands. The reasons for some of the troubles were that they refused to go on labour in a usual bonded form. This old slavery they did not want; they want to rebel against it. You will have to go into the causes as to why it took place. These are of special significance. The constructive suggestion is that the political parties must sit together and accpet certain responsibilities. It is not enough to tell a police station officer that you go and enquire about it. Well, that is one way of doing this. This is a police way of doing it. What I am trying to say is that there is something deeper and one needs to go into the matter much more fundamentally. We will have to find out many ways of dealing with it. It is not enough. If there are other forms of bonded labour, we will have to find it out and attack it ruthlessly if we can. As Government wants to attack law and order problems this is the worst law and order problem. Law and order problem has to be effectively dealt with—not when incidents start happening. They will have to deal with it at the root, go into the root cause of it. These are positive and constructive suggestions of doing it It is not enough to investigate the incident when it took place. It is necessary to see that such incidents do not take place. The people themselves in the villages, the higher castes in the villages should feel it their duty and responsibility, morally they should feel ashamed if such incidents do occur. Unless that sort of feeling in the country especially in the rural side is created, nothing will happen. This is a national programme; this is not a one-party programme. I do not say it is merely a Government programme. Unless of course, Government takes a lead in this matter, nothing is going to happen.

On the contrary, we find that merely certain technical explanations are being given about it. One feels that somebody is trying to justify. That is the worst part of it; that hurts the conscience of the nation; that hurts the pride of the people. That is the main point.

I would recommend you to read some of the correspondence between myself and the Prime Minister. The Prime Minister felt that I was merely trying to make a political capital out of it to raise it in the Parliament. I was totally dismayed. I wrote to him, "I must leave it at that. I do not want to carry on correspondence further". My intention was to establish some sort of a contact. I am mentioning to this correspondence only today. I am very glad that the members from the Government Benches have started raising this question. At least now he will realise that the question was not raised with any political motivation, with any party interest, but because it is a very serious question which is affecting the minds of the people at large and the nation as a whole.

I think, in our country, in the last one century, all the important leaders of our country, from Raja Ram Mohan Roy to the present days, have tried to create a public opinion about it. But even then we have not succeeded enough by merely creating a public opinion. Unless we create certain political social sanction behind all our efforts, nothing is going to make any further progress. Therefore, I thought it my duty to speak on behalf of my party and say that it is very well done by those who have moved this motion. It is good that now, today, it is not only one party speaking, it is the entire House speaking and it is the nation speaking on this issue of Harijans. I would request the Prime Minister, when he replies, that let him not merely speak because he has to justify a Government or a Ministry. He is more than a Prime Minister. I would expect him to look at the question from this point of view and go into the problem much more fundamentally and give us a programme.

As the Prime Minister, he can give us a programme, a programme for the nation, a programme for all the political parties. This is a non-party issue. This cuts across all the political frontiers or party affiliations. Let us create a situation in the country that the question of Harijans, the question of Girijans the question of minorities is given the same priority which it deserves.

Sir, I have done.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष जी, जहां माननीय चव्हाण साहब जैसे विरोधी दल के नेता अपने सौम्य और उदात्त भाव प्रदर्शित कर रहे हों, जहां हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी उपस्थित हों, और जहां सदन की सर्व-सम्मत भावना इस संकल्प के साथ जुड़ी हुई हो वहां बहुत अधिक कहना आवश्यक नही है। यह आवश्यक है कि अभी जो हमारे चव्हाण साहब ने कहा है कि इसको दलीय परिपेक्ष्य मे न रखा जाय बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में इसके निवारण के लिये प्रयत्न किया जाय। अखबारों की कतरने सब के सामने हैं, उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नही है। आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार से जिस कार्य को महात्मा गांधी ने शुरू किया था उनकी भावना को किस प्रकार से फिर पुनर्जीवित किया जाय। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हरिजन बन्धु गाय के रूप में उपस्थित है जिनकी पूछ पकड़ कर राजनीतिक वैतरणी तरने की हम सब कोशिश कर रहे है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय को टटोलें और कुछ रचनात्मक सुझावों के लिये हम अपने विचार उपस्थित करें।

अध्यक्ष महोदय, सचमुच में जो स्थिति है हरिजन भाइयों की वह बहुत दुखी है। कल सदन मे जो हमारे कुछ बन्धु बोल रहे थे, अभी भी हमारे बन्धु कुछ बोले, भले ही कुछ लोगों को अच्छा न लगता होगा, कुछ चाहते होंगे कि हिन्दुस्तान का विखंडन हो। लेकिन हिन्दुस्तान की सार्वभौम संसद् जिस समस्या को हल नहीं कर सकती तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी उस समस्या को हल नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, मैं उनकी भावनाओं के साथ अपने हृदय को जोडता हूं। सचमुच में विश्रामपुर, बेलची, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र में जो घटनायें हुई हैं अगर मैं अथवा मेरा परिवार उन के शिकार होते, तो मेरा हृदय किस प्रकार से उद्विग्न रहता? "आरत काहू न करे कुकरमा"। उनका हृदय विदीर्ण है। इसलिए उन की जो वाणी निकलती है, उस की मै केवल एक आक्रोश की वाणी समझता हूं, यथार्थ वाणी नही मानता हूं।

लेकिन इस का मतलब यह नही है कि हम इस समस्या को यहां पर पूर्ण विराम दे दें। दुख तब होता है, जब हम इस समस्या का राजनीतिकरण करने लग जाते हैं। प्रधान मंत्री जी और विरोधी दल के सभी नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या पर एक राष्ट्रीय बैठक होनी चाहिए, जिसमें सब लोग अपने रचनात्मक सुझाव दें। बेलची की घटना हो जाने के बाद वहां का पोस्ट मार्टम करने से हरिजन भाइयो का कल्याण नहीं हो सकता है। प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर। इसलिए मै आप की सेवा मे कुछ सुझाव रखना चाहता हूं, हालांकि हमारे विद्वान महान नेता अपने सुझाव रखेंगे।

सब से पहली बात यह है कि इस बारे में हम क्या एहतियाती कार्यवाही करते है, हरिजन भाइयो पर कोई जुल्म न हो, इसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्ज लेते है। हम ने कहा है कि जिलाधीश और जिला आरक्षी अधीक्षक इस प्रकार की घटनाओं के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। लेकिन अभी तक जहां-जहां ऐसी घटनाएं हुई है, वहां के जिलाधिकारियों अथवा जिला आरक्षी अधीक्षकों के विरूद्ध कौन सी कार्यवाही हुई है, यह सोचने और समझने की बात है।

आज हरिजन बन्धुओ को जिस प्रकार जलाया गया है वह आजाद हिन्दुस्तान के लिए कभी स्वाभिमान का विषय नहीं हो सकता है। कानून मंत्री बैठे हुए हैं। उन से मेरा निवेदन है कि जब मानवों को जलाया जाता हो, तो

[डा० रामजी सिंह]

ऐसे मामलों में समरी ट्रायल होना चाहिए। जब अदालतों में लम्बी कार्यवाही चलती है, तो ये दरोगा या थानेदार बिक जाते है, जिस के कारण हरिजन न्याय प्राप्त करने से वंचित रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों के लिए समरी ट्रायल हो और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दो तीन महीने में कार्यवाही होनी चाहिए।

हरिजन बन्धु गरीब है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वही सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें कानूनी सहायता दी जाय, केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि उसके लिए धनराशि का आवंटन हो, ताकि जो सामन्त लोग उन पर अत्याचार करते हैं और हजारों रुपयों के वकील रखते हैं, हरिजन उनका सामना कर सकें।

लेकिन जैसा कि हमारे महान् नेता, श्री चव्हाण ने कहा है यह सरकार का ही काम नहीं है जनता का भी काम है। जनता को भावनाओं को जिस प्रकार बापू जी ने झकझोरा था, शायद आज हम उस की ओर मुखातिब नहीं हो रहे हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी और सब लोग मिल कर फिर एक बार हरिजन और गिरिजन भाइयों के लिए कुछ करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि युधिष्ठिर अपने कुत्ते को छोड़ कर भी स्वर्ग नहीं जा सके, और हम भी अपनी आबादी के पंचम हिस्से का छोड़ कर भारतवर्ष में सुख और शांति से नहीं रह सकते।

कल कुछ हरिजन भाइयों ने कहा कि स्वर्ग इस विषय पर क्यों बोले। वे ऐसा नहीं कह सकते। मैं विनय के साथ कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य है कि मानव ने मानव को जलाया। लेकिन यह उस का सौभाग्य भी है कि बापू और दूसरे महापुरुषों ने, जो हरिजन नहीं थे, हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया। इसलिए हरिजनों की समस्या राष्ट्र की समस्या है। हरिजन और गैर-हरिजन, हम सब, मिल कर इस समस्या से लड़ेंगे और संविधान के नाम पर शपथ लेंगे कि हम इस को दलीय राजनीति के लिए शोषण का अखाड़ा नहीं बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी आप के सामने मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। सचमुच में ऐसी जो कुछ घटनाएं हुई हैं जैसे विश्रामपुर की घटना कितनी दर्दनाक घटना है। एक गांव के लोग नहीं, कई गांवों के लोग वहां जमा हुए और उन्होंने वहां उन को जलाया। मैं कहता हूं कि अगर भारतवर्ष में कोई न्याय की कीमत है तो उस इलाके में सामूहिक जुर्माना भी होना चाहिए।

इस संबंध में चव्हाण साहब ने ठीक कहा कि यह केवल सामाजिक सवाल नहीं है, आर्थिक सवाल है और सचमुच में अगर किसी भी प्रशासन में, इंदिरा जी के प्रशासन में भी अगर गरीबों और हरिजन भाइयों को जमीन दी गई तो देनी चाहिए, अच्छी बात है। यह अलग बात है हम लोग बिहार के हैं, कोई राजनैतिक शोषण के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि जितने परचे दिए गए थे उस में 60 से 40 प्रतिशत परचे कंवल परचे रह गए, जमीन पर उन का कब्जा नहीं मिला और आज कहते है कि उनकी जमीन से हटाया जा रहा है। इसलिए सचमुच में अगर उन को देना है तो सही ढंग से देना चाहिए। मुख्य बात तो यह है कि जब तक हिन्दुस्तान की आर्थिक परिस्थिति नहीं बदलेगी, भूमि-सुधार के कानूनों का प्रगतिशील कार्यान्वयन नहीं होगा, तब तक यह सामंती ढांचा बना रहेगा तब तक हरिजन और जो पिछड़े हुए लोग है, जो हमारे अन्त्योदय के भाई है वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते है।

लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि यह अस्पृश्यता का प्रश्न कहां से आया? यह कि यह अस्पृश्यता का प्रश्न हिन्दुस्तान की सड़ी गली जाति व्यवस्था से आया। गीता में कहा है—

चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्॥

यह जो चातुर्वर्ण्य की बात कही गई है, चार

वर्ण तो रहे, लेकिन वर्ण-व्यवस्था नहीं है आज। आज वर्ण-अव्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था की विकृति से जाति-व्यवस्था पैदा हुई। जाति व्यवस्था की गर्हित और कुत्सत चीज जो है उसी को अस्पृश्यता कहते हैं। इसलिए बापू के शब्दों के साथ में अपने विचार समाप्त करना चाहूंगा। उनके हृदय में कितनी ज्वाला है आप देखें। इस अछूतिस्तान की मांग में आप के आक्रोश में वह शब्द नहीं है, इस में आपके हृदय की पुकार नहीं है क्यों कि भारत-माता को विखंडित करने वाला भारतवासी नहीं हो सकता। लेकिन बापू ने कहा था—

"यदि अस्पृश्यता के काम रहने के कारण मुझे हिन्दू धर्म छोड देना पड़े तो मै जरूर छोड़ दूं और कलना पड़ लू या बापतिस्मा ले लू। पर मुझे तो अपने धर्म पर इतनी श्रद्धा है कि मुझे उसी में जीना और उसी में मरना है। सो इस के लिए फिर मुझे जन्म लेना पड़े तो मै भंगी के ही घर लूगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहकहता हूं कि सचमुच में यह भारतवर्ष हमारा घर है और इस को हम अच्छा बनाएंगे। इस को छोड़ने की बात कह कर के सम्पूर्ण राष्ट्र के दुख को आप बढ़ावेंगे नहीं। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस का विचार विमर्श होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

"अमृत बरसे शीघ्र नहीं तो रेगिस्तान रिसाता है।" आपको समय नहीं खोना चाहिए।

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): Mr. Speaker, Sir, I rise today with a feeling of pain and of gratification to participate in this debate—pain because of the blood-curdling cruelty that continues to be meted out to a section of our brethren and gratification because of the very heartening response that is seen in the House, irrespective of the Party distinctions. Whether belonging to the ruling Party or the Opposition Party, the reaction to these incidents has not been prosaic, formal or perfunctory, but something which is coming out deep from the heart. This shows that the heart of the nation is one as far as this question is concerned. This gives us hope that we will be able to solve this problem. As was pointed out by Mr. Chavan, this is a real national problem which we will have to look at from the national perspective.

I am remined of the great role of Mahatma Gandhi played in this respect. A section of the people who were the scum of society were exploited, bound down, enslaved and treated as worse than criminals or animals. Gandhiji came forward and gave them the name of 'sons of God' or 'Harijans'. He completely identified them as such and he gave us the philosophy and the message that until and unless they are raised up and treated as more than equals by making up for all the evils that were done against them through the centuries, he told us that this country will not attain Swaraj.

When the fathers of the Constitution wrote down the Constitution, there was a message coming out of it. We gave ourselves a Constitution to enshrine justice and equality—social, economic and political. Art. 15 took care that special provisions must be made for them and, in making them, equality of job opportunities need not be treated as violated. Art. 46 says that they may be taken special care of. Not only that, but it charges the State with the responsibility of protecting them against injustice and exploitation. There are Articles 338 and 336 making special provision for special office, a special provision for a Commission and making special provision for treating them in a special manner, and making special provision that there must be a Ministry in Orissa, Madhya Pradesh and Bihar to look after the welfare of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes.

[Shri C. M. Stephen]

I am pointing out all this to show that, from out of the Constitution, there is a message flowing out, a message not of formality but a message of solicitude. Even as a father will take care of his weak son, here is a class of people who through the historical process of centuries were ill-treated and brought down to the last base and, when the country became free, its responsibility is not merely to treat them as just one among others but to treat them as the weakest among us, needing and deserving special solicitude: that special solicitude which the weakest child of the family is expected to get from the father, is what the Constitution demands of us.

Thirty years have gone by. Let us not be in a mood of recrimination and mutual accusation. Let us be in a mood of introspection and mood of painful survey of the whole scene. Comparisons are absolutely cruel when we treat of a mater like this—what was the position in such and such a year and what is the position in such and such year. That bespeaks of an attitude which does not conform to, and which is not in tune with the message that I made mention of. Here, this House had many occasions to discuss this matter. After this Lok Sabha, under your presidentship, started functioning on one basic or the other we had occasions to discuss this matter but it so happens that no sooner a discussion is over than we hear another story of another batch of Harijans being burnt alive, another story of another set of Harijan women being raped and a story of cruelty committed on Harijans. This bespeaks of a national malady. Day before yesterday I read in the press that in Madras, in the Assembly, a discussion took place—that the wife of a Harijan, the wife of a Deputy Collector who happens to be a Harijan, was disrobed in public.

Attempts are made to justify it as a Holi prank. Holi prank can go against the wife of a Harijan and not against any other high caste person. Here is a justification coming, Sir. I am saying, let this House, let everyone of us sit back, examine and analyse the basis of this malady. I do not want to show an accusing finger against anybody, but I felt ashamed, pained, when I heard the crude comparison in terms of percentages and statistics. Fifteen percent of the people—only one percent of the crime has been put on them indicating thereby that fourteen percent of the crime is still due to them. Is that the way this question is to be approached? Is that the way that somebody who is put incharge must approach this? I had expected a mental revulsion coming up in complete protest that our brethren are being treated crually. Is this this approach expected of us? But I am heartened that that approach is not reflective of the mind of the nation, not reflective of the mind of the House; glory to this House, glory to this nation that this approach is not reflective of the mind of the nation and there lies the hope for this nation. Any steps absolutely necessary must be taken.

A demand was raised here that there must be a special Ministry to take care of them. If amendmen of he Constitution is necessary in case what is provided is not sufficient, that will have to be thought of. There is already a provision for collective fine wherever untouchability is practised or cruality is heaped on. Who has ever invoked this provision? Except in Gujarat in one instance, I have never heard of this collective fine process being imposed. This matter of collective came in Bombay Presidency, when Shri Morarji Desai himself was the Chief Minister. This provision was brought in and I felt proud when I hear Shri Mararji Desai making an announcement that he would go on a hunger strike if this thing is stopped. That sort of thing can certainly correct upto a certain extent.

I do agree that this is a matter which must be treated as above party. Anybody who ill-treats Hariajns must be treated as a criminal of the first water and must be approached as a special

leper who must be put down with the strongest hand. It is this approach that is necessary. The discussion that has taken place here during three days must carry this message to the nation, and this message is being carried to the nation, where the Government, Opposition and everybody agrees also not to make political capital out of it. I, on my part, say, that I approach it, not a spirit of making political capital out of it, but in a spirit trying to solve this problem. That is all I have to say.

As said by some hon. friends on the other side, the nation is today on the tip of a volcano. We can face an enemy and survive, we can solve certain other problems and survive, but if discontentment and frustration is there from Kashmir to Kanya Kumari among a large section of the people, whose sweat gives bread to this nation, sure as anything, this country is in for a complete explosion, out of which there can be no survival Therefore, this is indicative of the grave danger that we are facing and with a spirit of facing the danger, we huve got to approach this problem.

I may again repeat, as I said on the previous occasion, that the solution to this problem is for them to organize themselves and to assert their rights Nobody can help unless they help themselves They should organize and assert themselves, because they are the base of this country; they are not to seek and to beg, but to organize and assert. This is because it is on their shoulders that this country can exist and survive. If they assert themselves, nobody can suppress them. It is for the others to come along as Gandhiji did saying, "We are with you and together; either we sink or together we swim". That attitude can take us across. I on behalf of my party, put on record our deepest resentment against whatever is going on and we pledge our full support to any efforts that may be made to solve this problem constructively. We extend our hands of support to find a solution to this problem because it is a national problem, the solution of which is a desideratum if the nation has to survive. In that spirit, I support this motion.

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से हरिजनों पर अत्याचारों की वारदातों की बहुत ही हृदय-विदारक चर्चाएं यहां पर हो रही है और यह ठीक है कि दिन प्रति दिन हरिजनों के प्रति जो घटनाएँ घट रही हैं, उन मे कोई कमी आने का प्रश्न नही उठता है। इसलिए 'नही' कि पिछले 30 वर्षों से जब से हम स्वतन्त्र हुए है, तभी से जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति मे बदलाव आना चाहिए था, वह नही आया। अब प्रश्न यह है कि किस तरह से सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदला जाए क्योकि बगैर उसके बदले अत्याचार में, अन्याय में, असमानता में कमी नही हो सकती। मैं आप से निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिनके कारण यह असमानता बनी हुई है और जो अन्याय हो रहा है, यह केवल कानून के बस की बात नही है। हम महात्मा गांधी जी की चर्चा करते हैं। महात्माजी ने साबरमती आश्रम में जो हरिजन उद्धार के सिलसिले में प्रयोग किया, वह सबको मालूम है। वह एक भूमि थी, जहां पर यह काम आरम्भ हुआ। उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया और जो हरिजन उद्धार के कार्यक्रम थे, उन को आगे बढ़ाया। न केवल उन्होंने इस देश को राजनीतिक चेतना प्रदान की बल्कि उन लोगों के बौद्धिक, सांस्कृतिक स्तर को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया और न केवल अपने संस्कार से और अपने आचरण से बल्कि 'यंग इन्डिया', 'नव-जीवन' और 'हरिजन सेवक' आदि पत्रिकाओं को निकाल कर व्यापक रूप से उन्होंने प्रचार का काम किया।

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि जो घटनाएं घटती हैं, उस की खबर पुलिस में शीघ्र पहुंच पाती हैं या नहीं, यह देखने की बात है। आज गांव

[श्री युवराज]

में जो काम करने वाला चौकीदार है या दफादार है, जोकि निश्चित रूप से शोषित और दलित वर्ग का एक साधारण आदमी होता है, ऐसी घटनाओं की खबर शीघ्र नहीं दे सकता है। और अगर देता भी है तो बहुत देर से वह खबर पहुचती है और इसका कारण क्या है। उन को तन्ख्वाह कितनी मिलती है। हमारे यहा उनको केवल 70 रुपए महीना मिलते है।

कई माननीय सदस्य हमारे यहा तो केवल 10 रुपये मिलते है।

श्री युवराज अभी हमारे यू०पी० के माननीय सदस्य बतला रहे है कि उनके यहा केवल 10 रुपये मिलते है। हमारे यहा बिहार मे उन को 70 रुपये तन्ख्वाह मिलती है। ऐसे लोगो के हाथ मे अत्याचारो की खबर देने का काम है। जब उस का इतनी कम तन्ख्वाह मिलती है तो वह अपने गाव के धनी आदमी के पास जाता है और उस से वह अपने खाने के लिए दो सेर, चार सेर अनाज ले आता है। वहा उसकी पत्नी काम करती है और उन के यहा उस के भाई और लडके काम करते है। जब दो सेर, चार सेर गेहू वह अपने खाने के लिए वहा ले लाता है, तो वह उन लोगो के खिलाफ क्या शिकायत करेगा। जब इस तरह से आर्थिक असमानता बनी रहेगी, जो हमारा भूमि सुधार का कानून है, जो हमारा मिनीमम वेजेज एक्ट है, ये सब ठीक से कार्यान्वित नही होगे, तब तक जहा ये घटनाए घटती है, उन की खबर काफी विलम्ब से पहुचेगी। जो गाव मे चौकीदार है या दफादार है, वह घटनाओं की सूचना नही दे पाता है। बहुत बूढे लोग इस काम मे गावो मे नियुक्त हुए हैं और वे लोग खबर नही दे पाते हैं। धनी लोगो से उनको दो सेर अन्न मिलता है, तो वे उन के खिलाफ खबर नही दे पाते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हू कि आज जो ये घटनाए घट रही हैं, उन को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियो मे परिवर्तन लाने के लिए हम को पहल करनी पडेगी। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बदलाव करना होगा। लेकिन जिनके हाथो मे सत्ता है, उनकी बडी जिम्मेदारी है। यह ठीक है कि सत्ता मे रहने वाले लोग केवल इस काम को नही कर पायेगे। हम सब लोगो को मिल कर इस काम को करना होगा। नही तो यह काम नही हो सकेगा।

19 00 hrs

अध्यक्ष महोदय, इस बात की भी जरूरत है कि जहा यह घटना होती है वहा इससे सख्ती के साथ निपटना होगा। जो लोग अपराधी है, उनको दण्ड देना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नही होगा कि केवल छानबीन कर ली जाए या कोई कमीशन बिठा दिया जाए। हमे आर्थिक और सामाजिक पुनर्रचना का कार्यक्रम भी तीव्रता के साथ लागू करना होगा। इस कार्यक्रम को लागू करने मे केवल इतना ही पर्याप्त नही होगा कि हमने लेण्ड सीलिंग का कानून बना दिया है। हमे भूमि-हीनो को भूमि देनी होगी। उन्हे घर बनाने के लिए जमीन देनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जितनी भी घटनाए घटती है उन सब के पीछे कोई न कोई सामाजिक और आर्थिक कारण होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम देश के तमाम मुख्य मत्रियो का एक सम्मेलन बुलाएं और बुला कर उनसे कहे कि वे मुस्तैदी के साथ इस समस्या का समाधान करें। इस समस्या का समाधान उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान से ही सभव हो पायेगा। मुख्य मत्रियो से आपको यह कहना होगा कि प्रान्तो मे जितने भी कानून इस सम्बन्ध मे बनते हैं उनका उन्हें कठोरता से पालन करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग प्रान्तों में जाते हैं तो हम लोग जा कर के सर्किट हाऊसों में ठहरते हैं। अगर गांधी जी आज होते तो उनका आज एक अलग आन्दोलन होता। अगर वे होते तो उनको इस समस्या को सुलझाने का अलग ही रास्ता होता। वे आज के शासकों की तरह मूकदर्शक बन कर न रह जाते। गांधी जी को केवल कानूनी कार्यवाही से ही संतोष नहीं होता। इसलिए मैं अपने मंत्रिमण्डल के लोगों से, राज्य मंत्री से, और जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उनमे कहना चाहता हूं कि वे जहां भी दौरे पर जाएं तो वे किसी हरिजन के गांव में जा कर रुकें। वहां ठहरें और देखें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। उसके बाद वे समाधान करें कि उन्हें उनकी समस्याओं का कैसे समाधान करना है। आज हरिजनों के गांव में पानी नहीं है। पानी के लिए उन्हें गांव के बड़े, धनी लोगों के ट्यूबवेल पर निर्भर करना पड़ता है। जब हम सभी लोग हरिजनों के बीच में जा कर रहेंगे तभी हमें उनकी समस्याओं का पता चल सकेगा। हमें उनके जीवन में निकट से झांक कर देखना होगा। हम सभ्यता और संस्कृति की बड़ी दुहाई देते है और उसी से संतुष्टि कर लेते है। लेकिन कदम-ब-कदम पर इनके आदर्शों पर आचरण नहीं करते।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर काफ़ी गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और स्वयं प्रधान मंत्री जी बहस का उत्तर देने आये हैं इसी से यह अंदाजा लगता है कि सरकार इस समस्या के समाधान के प्रति कितनी सचेष्ट है और सरकार के दिल में कितना दर्द है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हरिजन का प्रश्न सारे देश में पैदा हुआ है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि दुनिया में जितने देश हैं, इतिहास निकाल कर हम देखें तो सभी जगह इस प्रकार की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, कमो बेश में, चाहे सभ्यता का ढोंग भरने वाले पश्चिमी देश हों और चाहे हिन्दुस्तान हो। वहां के नीग्रो, यहां के हरिजन, चाहे अफ्रीका का और चाहे रोडेशिया का हो। दुनिया के सामने यह एक प्रश्न पैदा है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। और हिन्दुस्तान में जो हरिजन समस्या है इसका निराकरण करने पर बहस कम होती है, बल्कि इन समस्याओं को उभारने का काम ज्यादा होता है। हम हरिजन अत्याचार पर रोयेंगे, आंसू बहायेंगे, आक्रोश में उत्तेजना में बहस करेंगे। उससे समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। अगर समस्या का समाधान निकलना है तो मैं यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान में जो जाति व्यवस्था है उसने केवल प्रशासन को ही ग्रसित नहीं किया है बल्कि हिन्दुस्तान की न्यायपालिका पर भी अपना असर डाला।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गहराई के साथ देख रहा था तो मैंने देखा कि बिहार में जो आंकड़े आये 1967 में जुल्म 74, चार्जशीट 52 में और अदालत में अपराधी को सजा केवल दो केसेज में। 1968 में जुल्म 84, चार्जशीट 51 केसेज में अदालत में केसेज गये और सजा केवल 5 केसेज में, 1970 में 83 जुल्म, चार्जशीट 63 में और सजा शून्य। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक जगह का रोग नहीं है। अपराध होते हैं, एक तो पुलिस चार्जशीट कम देती है, और देती भी है तो न्यायपालिका में जा कर हरिजन पर जुल्म करने वाला अपराधी रिहा हो जाता है, इसलिये अपराध करने वाले का मनोबल ऊंचा होता है कि हरिजन के मारने पर जेल नहीं मिलेगी। दो, तीन साल केस में जायेंगे और अगर 50 रुपया जुर्माना होगा

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

एक बीघा जमीन लेब कर मुकदमा लड़ते रहेंगे, लेकिन हरिजन पर अन्याय करेंगे। इसलिये सजा होना जरूरी है। जैसा माननीय रामजी सिंह कह रहे थे समरी ट्रायल होना चाहिये।

मैं बिहार के मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जैसे बिसरामपुर की घटना हुई, 7 दिन के अन्दर चार्जशीट दाखिल कर मामले को सेशन्स कोर्ट में दे दिया गया। इससे जल्दी और क्या हो सकती है। इससे पहले हरिजन को जलाने पर 10 दिन के अन्दर उस केस में सेशन्स कमिट कर दिया गया। बिहार की सरकार और मुख्य मंत्री बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और जगहों की मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन बिहार के मुख्य मंत्री स्वयं घटनास्थल पर जाते हैं। उन्होंने एक हरिजन सैल स्थापित किया है जिसका इन्चार्ज हरिजन नहीं है, मैं आपको बताऊं उस अधिकारी का नाम के० बी० सक्सेना है जहां हरिजन वाली कोई घटना होती है वह मौके पर जाते हैं, 5, 7 दिन के अन्दर केस को सुपरवाइज कर के सेशन में मामला दे कर तब सेक्रेटेरियट को वापस आते हैं। यह कार्यवाही करने के लिये संकल्प और इच्छा भी होती है।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर हम चाहते हैं कि हरिजन के ऊपर से अन्याय मिटे तो सबसे पहले हमको अपने दिल को भी साफ़ करना पड़ेगा। हम संसद सदस्य हैं, मेरे क्षेत्र के अन्दर अगर हरिजनों पर जुल्म की कहीं कोई बात होती है, सूचना मिलती है तो हिम्मत के साथ कहना चाहिए चाहे हमारा समर्थक हो क्यों न हो, लेकिन यह कहना चाहिये कि अगर हरिजन पर अत्याचार होगा तो सामूहिक रूप से वहां सत्याग्रह करेंगे, उस अत्याचारी का सामाजिक बहिष्कार करायेंगे और उसका हुक्का पानी बन्द करायेंगे, मजदूरी बन्द करा देंगे और उसको खेती आबाद नहीं होने देंगे। अगर सामाजिक मुकाबला करने की हम में शक्ति होगी तभी मुकाबला होगा। लेकिन हरिजन के लिये आंसू बहा कर, अपने दरवाजे पर कोई हरिजन आये तो उसको सम्मान न दें, हरिजन की बात तो करें लेकिन जो गरीब अपने घर की बगल में हो उसको बराबरी का सम्मान न दे, यह दो तरह की बातें देश में होती रही हैं। कथनी और करनी में भेद चलता रहा। एक तरफ़ कहा गया सम्पूर्ण जगत ही ब्रह्म है, दूसरी तरफ इन्सान को अपवित्र कहा गया, यह सिद्धान्त में कुछ और रहा, व्यवहार में कुछ और रहा।

इस सदन और सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर वे हरिजन-समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो वे ईमानदारी से जाति-व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करें, जो हिन्दुस्तान का सब से बड़ा कोढ़ है। इस के लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाये। संसद-सदस्य मिल कर सरकार पर यह दबाव डालें और जनमत तैयार करें कि जब तक अन्तर्जातीय विवाह नहीं होंगे तब तक जाति मिट नहीं सकती है और इस लिए अन्तर्जातीय विवाह को सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया जाये। ऐसा करने पर जाति टूटेगी और हरिजन तथा हम सब बराबर होंगे। रामधन की बेटी की शादी और मेरी बेटी की शादी जब एक जमात में होने लगेगी, तो न वह हरिजन रहेंगे और न हम सवर्ण रहेंगे। इसी तरह इस समस्या का समाधान होगा।

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से सदन में जो बहस हो रही है, उस में बहुत से आंकड़े दिये गये हैं। आंकड़े मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन आंकड़ों को यहां रखने की कोई जरूरत नहीं है।

आज जो घटनायें घट रही हैं, उन पर विचार करते हुए हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि पिछले तीस सालों में क्या

हुआ है और पिछले एक साल से क्या हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि 1 परसेंट जुल्म हो रहे हैं या 15 परसेंट हो रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के शब्दों में अगर हिन्दुस्तान में कहीं एक भी ऐसी घटना घटती है, तो हिन्दुस्तान के लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। अगर हम इन घटनाओं को बहुत लाइट वे में ले रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर हम इन घटनाओं को पृष्ठभूमि में जायें, तो हमें कुछ और ही चीज देखने को मिलेगी।

आज इन घटनाओं के कारण जो ज्वालामुखी इस देश में सुलग रहा है, अगर वक्त रहते इन घटनाओं को न रोका गया, और वह ज्वालामुखी इसी तरह सुलगता रहा, तो कहीं एक दिन ऐसा आये कि वह ज्वालामुखी फट जाने और उस की लपेट में पूरा देश ही आ जाये।

जैसा कि मैंने कहा है, हरिजनों पर कहां कहां और कैसे कैसे हमले और अत्याचार हो रहे हैं, उन की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन इस समय मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या क्या करना चाहिए।

मैं राजस्थान से चुना हुआ हूं और राजस्थान में सब से कम घटनाएं घटी है। जब से राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां आज तक कोई भी कत्ल की घटना नहीं हुई है, और उस का एक कारण है पिछले कुछ दिनों में राजस्थान सरकार ने जो कार्य किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार यह काम किया कि एक हरिजन को अपना होम मिनिस्टर बनाया, जिस से वहां के लोगों का जनोबल ऊंचा हुआ और बने हुए तमा पिछड़े हुए लोगों ने महसूस किया कि हमारा आदमी आज होम मिनिस्टर बना है। और जो दूसरे लोग थे उन लोगों को कुछ भय हुआ कि नहीं, अब सम्पत राम हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि हर राज्य के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर ऊंची जाति का है तो होम मिनिस्टर शेड्यूल्ड कास्ट का होना चाहिये, अगर कलेक्टर शुड्यूल्ड कास्ट का है तो डिप्टी कलेक्टर ऊंची जाति का होना चाहिए, दारोगा अगर ऊंची जाति का है तो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का आदमी सब-इंस्पैक्टर जरूर होना चाहिए।

पुलिस के अंदर या अदालतों में जो मामले जाते है उन में जातियों का कोई हवाला न हो। जब आदमी अदालत में या कहीं पर भी जाये तो उस की जाति न पूछी जाय और हरिजन शब्द का प्रयोग तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। मैं पंजाब की गवर्नमेंट को जो उन्होंने यह आर्डिनेन्स लागू किया है उस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और हिन्दुस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि पूरे देश के अंदर यह चीज लागू की जाय कि किसी भी आदमी की जाति न पूछी जाय। चाहे स्कूल में हो या कचहरियों में या किसी भी जगह हो उस की जाति न पूछी जाय। जिस गांव में शेड्यूल्ड कास्ट पर अत्याचार हो उस गांव पर सामूहिक जुर्माना होना चाहिए और वहां पर जो प्रधान है उस को डिस्क्वालिफाई कर देना चाहिए कि वह जिन्दगी के अंदर कभी भी प्रधान न बन सके।

मैंने यह कुछ सुझाव दिए है और मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस के ऊपर गौर करे। इन के ऊपर वह अमल करे और देश के अंदर जो असुरक्षा की भावना बढ़ रही है उस को बढ़ने से रोके।

MR. SPEAKER: The Prime Minister.

श्री शंकर देव (बोदर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम वहां पर है और बहुत दिनों से है। मेरी शिकायत है कि मुझे टाइम नहीं दिया गया। कल भी यह बात कही गई थी कि टाइम दिया जायेगा लेकिन नहीं दिया गया।

MR. SPEAKER: We have given six hours to this debate. All the 544 Members cannot get a chance.... (*Interruptions*) I have already called the Prime Minister.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Mr. Speaker, it is a matter of great pain for me to hear all that I have been hearing now and to know what was spoken in the first four hours when I could not be present here.—Painful not because Government is abused or that Government is blamed, but painful because such things should happen at all and that there should be occasions for such debates. One feels ashamed before the world because all this news goes to the whole world. It is not at all a matter of statistics in my view. But statistics have been given because that is how they were provocatively cited. There should be no provocation, I do agree. But after all, those who are in charge of Government are also human and if they are attacked persistently without any fault, they are bound to feel sore about it. Why is it not understood by my friends who also have a feeling of legitimate soreness. But I do not want to dwell long on it.

I see the hon. Leader of the Opposition, who spoke and found fault with what I had written to him in this matter has gone away, may have gone away for some work, but it would have been better if he had been here.

SHRI K. GOPAL (Karur): Actually he wanted to be here. But he has some other work.

SHRI MORARJI DESAI: Then he should not have spoken.

SHRI K. GOPAL: He has some other work.

AN HON. MEMBER: Why is the Home Minister not here?

SHRI MORARJI DESAI: I am here for the Home Minister. The Home Minister is not here because it is not that the Home Minister does not want to be here, but it is painful to hear things which are being said and one does not want to get provoked. I am here and I have said that I will reply to it. As it is a censure against the Home Minister, it is a censure against me. I cannot hold the Home Minister more responsible for it than I hold myself or the Government. But it is a matter which must be considered not in anger but in a more quite atmosphere than we are doing. That is what I would like to plead, if I may say so. When the Leader of the Opposition said that I had written to him that this is a national question, not a political question, he felt angry about it and wrote to me that it is no use writing to me. That is what he repeated here. He gives me a compliment which I believe he does mean. But if that is the way of giving a compliment, it would be better not to give the compliment. What did I say to him? I have said everything to which he had referred. In my letter, I said to him "I am very sorry that this should happen, it is a shame for all of us. These are national things and it does not relate to only one party or another, and we have got to exert for it." But when you send teams only to the areas where there are Janata Party Governments and you do not send teams to the areas where your people are running the State Governments, what am I to consider? It is not a matter which refers to only one State. It is a blot on the whole of India. In all parts this is happening, not happening now, it has been happening for many many years. But that is no justification for its continuance. I do grant. But is it imagined that we can solve this problem by blaming those who cannot be blamed for it or by criticising Government which is earnest about its solution? If that helps, I have no objection if this Government disappears. I want you to know this. It was suggested that I should have gone on hunger strike. If he convinces me that my going on hunger strike and giving up my life will solve this problem, I am prepared to do it tomorrow.

SHRI C. M. STEPHEN: You have misunderstood me. I was only saying that I felt proud when I read that you made that statement. Not that I want him to go on hunger strike. Let us not put it out of context. I was really feeling proud when he said that and when he felt so much. I said that I felt proud about it.

SHRI MORARJI DESAI: No. It is not my hon. friend who says that. There are others also who say that. I am not referring merely to him

SHRI C. M. STEPHEN I am sorry.

SHRI MORARJI DESAI: But there are some suggestions by some people. I would be prepared to do it tomorrow if my hon. friends in the Opposition think that that will help, that it will remove the evil; I will do it tomorrow and disappear and I will consider myself obliged to Government and the country that I have been able to utilise my life for this purpose.

May I say, Sir, that I understand the feelings of pain and anguish of my own collegues who are Harijans because they feel the pain which I do not? But that does not mean that they should rub it on me. This is all that I plead with them. After all, am I responsible? Is my colleague the Home Minister, responsible for it? I do not know why we are blamed for it Yes, we have not been able to remove this scourge within one year of office. And there are incidents taking place. Whether they are more now or they are less now is not a consideration which weighs with me. I have said so often that even if there is one incident, I will feel ashamed about it. This is a canker which has eaten into our vitals I have even said that it is because of these sins of our society, of our people in this country, that we have been suffering for all these centuries. We had lost our freedom and we are suffering even today because we are not able to wipe out this blot here. That is my feeling in this matter and I believe that is the feeling of all my colleagues. We have been taking steps, wherever this happens, to bring the criminals to book, because I call them criminals who do these things, and see that they are brought to book very thoroughly. But I cannot claim that Government machinery has become very efficient yet. Am I to blame for that inefficiency? I do not want to blame anybody. Why have I to do that and provoke more attacks or more criticism for nothing? That does not solve this problem. I do not say that those who preceded us in Government were callous to it. I cannot say that. They had their own limitations, but they expect that our limitations should not be there. That is why I say, this is being utilised as a political stick with which they seek to beat Janata Government which is not fair at all, which is not right. It does not solve the problem. it bedevils it further. And that is why I am saying please do not give any political turn, to it. We should sit down together, not in a big conference, but in a small group; for in a big Conference, the same things will be repeated Will that solve the problem? Let us sit down. a few of us, and go into it very thoroughly and take proper steps. But that requires a calmer atmosphere, and that requires willingness for it. But if it is sought to be said that all these incidents are due to this Government, or that this Government is lax about it, how am I encouraged to call such a conference? Because they will again utilize that opportunity for their purpose. That is my fear. I may be wrong, but I am human and so are my hon. friends human; but why should they assume that I am not human? Why should they assume that my colleagues are not human?

One of my friends even said that there should be a separate State. How can that be, but that is not going to benefit. (*Interruptions*) That does not. Whether he does suffer or not, he feels it more, because he belongs to that sect. I can understand

[Shri Morarji Desai]

his bitterness, but will that bitterness solve the problem? It would not solve the problem The problem will be solved by all of us making a concerted effort to remove it, and to suffer for it That is what we ought to do I have offered to my Harijan brothers that if they offered a satyagraha, I am prepared to join them even if I am the Prime Minister I have offered it because, I wanted to assure them that I am willing to do anything that I can do But I cannot make futile efforts, which will not produce any result but may have mere propaganda value It is not a matter of propoganda, but of intense pain and shame for all of us But it is not the creation of the present generation. It has been with us for hundreds of years, and it has gone on ever since

Somebody went on to say that even Gandhiji did not do well. I cannot understand a person who can say this Does he forget that until Gandhiji took up this question in 1915-16, soon after his arrival from Africa, there was absolutely no feeling in this country against it? There were our saints, men of religion who have been crying against it for centuries, and yet it had had no dent on the system at all It is only when Gandhiji took it up and aroused the conscience of the society that the dent has been made, the evil has been attacked and results became perceptible, for which you will find no parallel in any other country during the last 2,000 years But that is no satisfaction Let me say this, there cannot be any satisfaction until this curse disappears I want to see that casteism goes Otherwise, this curse cannot go And if this goes, casteism will crumble These are the two sides of the same coin in my opinion But that cannot be done by mere legislation We have all to work for it It is because all of us did not work as hard in Gandhiji's time, and after it, as we should have done, that the evil has not yet gone We are all responsible for it. I will accept my share of responsibility for it Whatever I may have done, I have been attacking it not only now, for many years, for more than 40 years, I have wrestled with this problem I have not hesitated, as a Minister of the Government in Bombay, to take strong actions Harijan boys and girls were not allowed to sit in schools They were kept separate They were not even given water from the same pots I took it up in the most turbulent district And we issued orders to close the schools where the villagers did not give equal status to the children of those communities I said if they do not give them seats the schools will be closed They were closed There was even litigation But they did not succeed. Ultimately they had to come round and the problem was solved They got a fair deal there But we had to make that effort

In my own constituency, very near my place the harijans were not allowed to draw water from a well which was used by other people I declared it to be a public well so that they were entitled to take water from it and gave police protection Then the other people said "we will not take water from this well, we will have another well of our own". I said "you can have a well, if you want, but these people will take water from this well' Then they gave up, because that was the best well and they all began to take water from it

I do not say this in order to show merely my earnestness I am only saying that in spite of taking many such steps I must admit, I have not succeeded as well, as I want to succeed in this matter and I feel it intensely But what is one to do? One has got to persist in it

When it is said it will be taken to the UNO, is there a sense of proportion? Can we be compared to Africa? Is Government encouraging these things anywhere? Is not Government

taking steps to prevent it? Yes, I must say, that we have not been able to devise measures which would stop the occurrence of these things.

SHRI T. BALAKRISHNIAH (Tirupathi): May I ask for a clarification? (*Interruptions*)

SHRI C. M. STEPHEN: Sir, why are they shouting? You are here to regulate the proceedings. I do not understand these things.. (*Interruptions*) What is this?

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): On an issue like this, why do you want to shout him down? (*Interruptions*)

SHRI MORARJI DESAI: Do not make it a harijan and non-harijan issue. Once a harijan.....

MR. SPEAKER: Once questions and answers start, it will go on endlessly.

SHRI T. BALAKRISHNIAH: Sir, I am a participant in the debate and I have got every right to put a question. I want definite information or answer from the hon. Prime Minister. Our hon. Prime Minister has said that if anywhere it is found that the Government is responsible for these atrocities, he will take action. But his own officers have said that they are helpless in the matter of putting down the atrocities, because the people who are the perpetrators of the crime are claiming that they enjoy the sympathy and support of the Government at the top. Tomorrow. I will show you the paper cutting.

SHRI MORARJI DESAI: I would request my hon. friend to let me know the names of those officers. I will dismiss them.

SHRI T. BALAKRISHNAIAH: Certainly. Tomorrow I will produce it.

SHRI MORARJI DESAI: I agree that steps have to be taken. But why does my hon. friend believe without verifying facts? I would like to know one instance where such a person has been supported by Government. And if any Minister has supported such a person, I will see that the Minister is not there. Why do you doubt it? So, that is not the question. Nobody has been supported. Why are imaginary charges being made? This is not the way at all. But everybody will not be able to reply and contain himself when he is under an attack, even when he does not deserve it. And if he loses he does not deserve it. And if he loses must sympathise with him. You may smile, you may laugh, it is only when one suffers one will realise. These are very serious matters and we have to take them very seriously.

It was said that there should be a separate Minister. Will that solve it? I am prepared to do it tomorrow. It will not. We have, therefore, appointed a Commission for it, and that Commission will be open to all of them.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Make a Harijan the Home Minister and tomorrow you will see the difference.

SHRI MORARJI DESAI: I have been a Home Minister for more than ten years, and I cannot claim that I have been able to finish this matter, and I do not think I was considered an Ordinary Home Minister. So, please do not have any prejudices and say that this is the remedy for it. This again is another dig at the Home Minister, which is very wrong. I must protest against it. This is not right. What is the meaning of saying these things? In such a situation a person will say something in self-defence. Then, the whole question gets blurred and only words remain. That is what happens. I would not like to do that, because these are things which cannot be justified on any account, whatever happens.

[Shri Morarji Desai]

We have got to put our heads together and see how best we can finish this evil, and that is where I would seek the co-operation of all friends.

I am aware that my hon. friends who have suffered are bound to be bitter about it. That does not help, but I cannot say that they should not be bitter. After all, I cannot feel as they feel, I have to admit it whatever my sympathy. Therefore, we must have patience with them. I would therefore plead with my hon. friends that if they want to be effective, this is not the way we can deal with this problem, this is not the way we can solve it. If they want to try to remove the Janata Party from Government, they will be the first victims if the Janata Party Government goes, let them understand. It will not benefit Harijans. It is not a question of Government or party. It is a question of the health of the nation, its honour and its self-respect. I believe that if the self-respect of even one person is hurt by me. I am not fit to serve anybody. This is what I hold and believe. And here it is not only self-respect which is wounded, but the very existence is at stake. Therefore, if people feel angry, we have to bear their attacks and find out ways and means to see that we do not allow such things to happen but we stop them altogether.

There are two ways of doing it. One is taking strong action against those who commit these crimes. Another is, for us to combine in those areas where these things happen to give strength to them and root out the evil in a nonviolent way as Gandhiji taught us. That would give them more courage.

It is said that when the Janata Party Government came, those people felt encouraged to do these things and that is why they are doing them. Does that not mean a political use of it? Have we asked them to do these things or are we conniving at them? Land was given, but given without proper precautions. That is a thing about which I have written to all the Chief Ministers. . .

SHRI SHANKAR DEV (Bidar): I am sorry. Lands have been allotted, definitely legally allotted and they were snatched away. Is he prepared to dismiss the Minister who has insulted all the scheduled castes and scheduled tribes by saying that only one per cent of atrocities have been committed? This is a great insult and we are not going to tolerate it.

SHRI MORARJI DESAI: May I say that instead of helping the process, it is halting the process? It is not going to help anybody. What have I said? I have said that I have written to the Chief Ministers that even if there are cases in which lands have been given in a wrong manner or should not have been given to them. .

SHRI SHANKAR DEV: He must be dismissed.

SHRI MORARJI DESAI: One can get mad with pain and sorrow but that does not help the pain and sorrow. Why get mad? That is what I am pleading. What I said was that even in such cases, they should not be vacated from the lands until they are given other lands which is suitable and which is good for them—not merely any land to be given, that I have said. I have also said that nobody should be allowed to take away the land by force whatever may be the reason, from them and they should be immediately dealt with. I am trying to keep track of such incidents and get reports. Ultimately, one has to see how best it can be done by them. I cannot dictate to people. I do not want to be a dictator.

SHRI C. M. STEPHEN: He is evading. We expect something else from the Prime Minister.

SHRI MORARJI DESAI: Is this not politiking? I am saying that steps have

to be taken. There are two kinds of steps and I am describing them and still my hon. friend, gets the impression that I am evading the issue. Why have I to evade this issue? Is this not politiking?

SHRI C. M. STEPHEN If this is politiking, there is going to be politiking.

SHRI MORARJI DESAI: My hon. friend can go on politiking I have no objection to it. I still seek his cooperation.

SHRI C. M. STEPHEN. That is there.

SHRI MORARJI DESAI· I know what is there. You are telling me this. I have far more experience than you have of public life. Therefore, I understand these things. But why get excited like this?

SHRI C. M. STEPHEN Why do you call it politiking?

SHRI MORARJI DESAI: I cannot mince words in these matters. I can do that with my Harijan friends but not with you.. .I will bear whatever they tell me but I would not take it from you.

SHRI C. M. STEPHEN. I do not expect any concession from you.

SHRI MORARJI DESAI: Let us be as clear as possible. I would be glad if it could be cleared. I have no objection to it. There is no question of any concession to anybody. Why does he talk like that? (*Interruptions*) I will deal with it; you need not bother. But I did say that wherever it has happened, strong action should be taken and the officer responsible for negligence should be suspended and disciplinary action should be taken against him to remove him. I have also said that this applies to officers in whose charge this happens.

SHRI SHANKAR DEV: The Minister must resign.

SHRI MORARJI DESAI Minister cannot resign for the fault of officers. Then every Minister will have to resign every day. Even if my hon. friend becomes the Minister, he will not last a day. This is what will happen. Therefore, why make a proposition which is impossible?

So we must strengthen them and see that they do not suffer particular harassment in the villages. In several places, they are depending on the whole village population for their living. Therefore, they do not allow them to do anything. We should see that they do not have to do that and see that they stand up for their rights in a non-violent manner. If violence comes in, it is not going to benefit anybody. I do not know if violence would solve the problem. It is so bad. It has to be solved. But I do feel that violence will not solve the problem. So, we have to take all steps necessary to see that this ends as soon as possible.

I seek the cooperation of my friends there Any suggestions that they would wish to make, I will give them respectful consideration. But, ultimately, I do think and, I hope it will be understood that I can act only on those suggestions about which I am convinced. We can discuss them. I am prepared to meet a few friends on this matter. It is not a question of the Government or the Opposition. This is a matter for all of us. We have, therefore, to meet and see that we find practical solutions for this problem.

I seek the cooperation of all my friends When I said that a political advantage is sought to be taken, I feel that that does not help. After all, it is the business of the Opposition to find fault with me. If they don't I do not consider them worth it. Therefore, that is not the question. The question is the manner in which the cause is to be served. That is all my

[Shri Morarji Desai]

plea. I do not know why my good friend gets excited. He cannot help it, he must get excited! Let him not do it. It will injure his health.

श्री बसन्त साठे (अकाला) : यह जो आध पौन घंटे का प्रवचन हुआ है, क्या इस में कुछ रीएशोरेंस निकला है ? (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं विरोधी दल के नेता माननीय स्टीफ़न साहब और साठे साहब आदि सब लोगों से आग्रह करूंगा कि वे यह न समझ लें कि हम लोगों ने जो इतनी गर्मागर्म बहस की है, इससे उन लोगों को कोई लाभ होने वाला है । उन्होंने तीस साल तक जो कूड़ा-करकट जमा किया है, जो गन्दा नाला बनाया है, उसी में इन कीड़ों का जन्म हुआ है। उन्हीं की नीतियों के कारण आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं ।

MR. SPEAKER: Mr. Paswan, let us keep a high level of the debate. Let us not get into another controversy.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह इन लोगों की देन है । इसलिए, आप इन लोगों को शान्त रखें ।

मैं कहता हूं कि आज कहा गया है कि इस को राजनैतिक भावना से न लें । सब से बड़ा कांड हुआ है बेलची का । उस से बड़ा कोई कांड पिछले कुछ समय के अंदर नहीं हुआ है । क्या मैं अपने कांग्रेस के माननीय साथियों से पूछ सकता हूं कि दिल्ली में बैनर ले कर, पोस्टर और पैम्फलेट बांट कर और अखबारों में निकाल कर के बेलची कांड का जो मेन अभियुक्त है इन्द्रदेव चौधरी उस की रिहाई की मांग नहीं की गई ? प्रदर्शन कर के 14 मार्च को मांग की गई कि इन्द्र देव चौधरी को रिहा करो । आप को शर्म नहीं आती है ? .... (व्यवधान) ...और आप कहते हैं कि इसको हम राजनैतिक भावना से नहीं ले रहे हैं । इन्द्र देव चौधरी की रिहाई की मांग की गई पटना में 14 तारीख को ।

इसलिये मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस को राजनैतिक भावना से हम न लें । यदि कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के हरिजन एम पी आज तक सतर्क रहते, तैयार रहते, जागरूक रहते तो हम लोगों को यह दिन देखने का मौका नहीं मिलता । हम लोग जागरूक हैं, कांशस है और अपनी सरकार के ऊपर भी सवारी करने के लिए तैयार हैं इसलिए कि हम लोगों को भी आप के ऐसा दुर्दिन देखने का मौका न मिले । माननीय प्रधान मंत्री जी जिन के प्रति हमारी सारी आस्था है, उन से मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन आप लोगों से मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जनता पार्टी की हुकूमत जिस के माध्यम से इस देश को नयी दिशा मिलने वाली है, देश में परिवर्तन होने वाले हैं, इस को आप पांच साल तक धैर्य के साथ देखें और उस के बाद जज करें, उस समय भी यदि हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो फिर आप नहीं चिल्लाइएगा, हम चिल्लाएंगे ।

मैं अपनी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । आशा है प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार उस पर ध्यान देगी ।

पहली बात तो यह है कि यह बात सही है कि घटना होती है । घटना घट जाना किसी के बश की बात नहीं है । लेकिन घटना घटने के बाद हम उस पर क्या कार्यवाही करते हैं ? हम ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि जिससे घटना घटे ही नहीं और इस के लिए मैं ने उस दिन सुझाव दिया था कि आज जो भारत सरकार के सामने लाचारी है, भारत सरकार कहती है कि हरिजनों और आदिवासियों का मामला, उन के ऊपर ऐट्रासिटीज का मामला स्टेट का मामला है,

हम उसमें डायरेक्ट इटरफेयर नहीं कर सकते हैं, उस संबंध में आप कानून में संशोधन कीजिए, संविधान में संशोधन कीजिए, जो नये उपाय खोजने हों वह खोजिए लेकिन स्टेट और सेंटर दोनों की बराबर जिम्मेदारी इस की रहे कि कोई घटना कहीं हो तो हम भारत सरकार को भी पकड़ सकें और वहां राज्य सरकार को भी पकड़ सकें।

दूसरी बात—बिहार के मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी, जगजीवन बाबू यहां बैठे हुए हैं, उन्हीं के समक्ष उन्होंने कहा था कि हमें दो चीज करनी होगी। पहली चीज यह कि या तो जितने गरीब हैं उन को हमें हथियार देना होगा और नहीं तो जितने पूंजीपति हैं उनसे हथियार छीनना होगा। बेमेल लड़ाई नहीं चलेगी। एक तरफ रायफल और दूसरी तरफ लाठी, यह लड़ाई नहीं चलने वाली है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में भी इस तरह की कठिनाई हो, जिन क्षेत्रों में भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो, जुल्म हो, उन क्षेत्रों में आज आप हथियार तो सब को नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उन से हथियार छीन लीजिए। वह हथियार भी क्राइम की, उत्पात करने की एक जड़ है।

तीसरी बात—हमारे साथियों ने सजेशन दिया है कि अत्याचार करने वाले की नागरिकता छीन ली जाय। मैं समझता हूं कि सरकार का इसमें कठिनाई नहीं होगी लेकिन जो माननीय सदस्यों की भावना है वह यह कि उस के लिए कठोर से कठोर दण्ड का विधान बनाया जाय। जो आदमी हरिजन के ऊपर या आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करता है, उस की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है उस के साथ में कठोरता से पेश आएं और उस के लिए स्पेशल कानून बनाने की बात हो तो स्पेशल कानून बनाएं।

मैं एक बात और सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मैं ने उस दिन भी कहा था कि जाति पांति का जन्म देने वाले ये मन्दिर और मठ हैं जहां बड़े बड़े शंकराचार्य और आचार्य बैठे हुए हैं। शंकराचार्य जैसे लोग पटना में और दूसरी जगह जाकर जातिवाद का बीज बोते हैं और कहते हैं कि यह जातिवाद जन्मजात आधार पर है। उस के लिए मैं ने उस दिन सुझाव रखा था कि एक रेलीजस इस्टीच्यूशन, धार्मिक संस्थान खोलिए और जिस तरह स्कूलों में पढ़ाई होती है उसी तरह उस में हरिजन का भी बच्चा पढ़े, ब्राह्मण का भी बच्चा पढ़े, राजपूत और बनिये का भी भी बच्चा पढ़े। जो उस में डिग्री ले कर निकले वह जा कर मंदिर में या मठ में या जहां भी शंकराचार्य या और जो आचार्य बनना हो वह बने। कभी कोई नहीं कह सकेगा कि यह ब्राह्मण है या हरिजन है। वहां वह आचार्य बन कर रहेगा। कोई समझेगा नहीं कि क्या है। इसलिए एक रलीजस इस्टीच्यूशन खोल कर के आप ऐसा कीजिए।

20.00 hrs.

चौथी बात—अभी सरकारी नौकरी की बात हम लोग करते हैं। लेकिन मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, सरकारी अर्ध-सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, उस में आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। आप ने केवल सरकारी नौकरियों में 15 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है और उस में भी कोटा पूरा नहीं होता है। उस में सूटेबिलिटी और अनसूटेबिलिटी का मामला आता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप आरक्षण की व्यवस्था करें। नौकरियों के मामले में अभी भी लिखा हुआ है—

[श्री राम विलास पासवान]

If a suitable candidate belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe is not available, then the vacancy will be de-reserved'

प्रधान मंत्री जी का चाहिये कि इस नियम का तुरन्त समाप्त करें। जब आप कहते है हरिजनो मे लाख से ऊपर ग्रैजुएट है लाखो पढे-लिखे लोग हैं प्रथम श्रेणी मे जाने लायक है तो ऐसी स्थिति मे इस प्रकार के नियम को रखने का क्या मतलब है ? इस प्रकार के नियम से अफसरो को गलत काम करने के लिये बल मिलता है। इस लिये मेरा आग्रह है कि इस नियम को तुरन्त समाप्त किया जाय।

इसके साथ मेरा आप से निवेदन है कि आप शेडयल्ड कास्ट्स और शैडयल्ड ट्राइब्स के लिए एक पाच वर्ष की योजना बनाये और इस प्रकार की व्यवस्था करे कि पाच साल के बाद इस देश मे कोई भी ऐसा हरिजन का परिवार नही रहेगा, जिसमे कम से कम एक आदमी या तो सरकारी नौकरी मे न लगा हो या किसी रोजगार मे न लगा हो। यदि आप इस प्रकार की योजना शुरू करेंगे तो हम समझेंगे कि आप वास्तव में क्रान्तिकारी काम कर रहे है। आप इस देश के सारे हरिजन परिवारो की लिस्ट बना लीजिये और यह व्यवस्था कीजिये कि पाच साल के अन्दर उस मे से एक आदमी या तो सरकारी नौकरी में होगा या कोई रोजगार कर रहा होगा।

जहा तक अनुसूचित जाति और जनजाति के कमिश्नर का मामला है आप देखे—कि कमिश्नर की रिपोर्ट कितने साल के बाद आई है। मैं सरकार से कहूगा कि यह बहुत बडा मामला है। कोई चीज बनाई जाती है तो उस के पीछे एक उद्देश्य रहता है लेकिन जब वह दबा दी जाती है तो सारा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। आप कोई भी नीति बनायें, पालिसी बनायें अगर उसका कार्यान्वयन न हो या उस का कार्यान्वयन करने वाले ठीक लोग न हो, तो कुछ भी नही लगा। मेरा सुझाव है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट प्रति वर्ष सदन मे आनी चाहिये और उस के साथ साथ एक्शन-टेकन रिपोर्ट भी पेश की जानी चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं एक सुझाव और रखना चाहूगा—जहा भी हरिजनो पर इस प्रकार के जुल्म होते है—सभी जगह पुलिस स्टेशन्ज बने हुए है। अगर आप उनकी रिपोर्ट ले तो वे कहेंगे कि हमारी क्षमता 30 केसेज की है हम 300 केसेज कैसे देख सकते है। जो डकैत है वे तो जीप पर आते है और हम साइकल पर जाते है तो हम उन का मुकाबला किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि हरिजनो पर जो अत्याचार होते है उन का मुकाबला करने के लिए आप स्पेशल सेल बना दीजिये। पाच सात पुलिस स्टेशन्ज मे एक सेल बना दीजिये जो हरिजनो के मामलो की तुरन्त कार्यवाही करे और तुरन्त अपनी रिपोर्ट दे और कोर्ट मे तुरन्त फैसला हो। इस काम के लिये अलग से पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमारे साथी श्री हुकुम देव जी ने अन्तर्जातीय विवाह का सुझाव दिया है। उस मे मेरा सुझाव है कि बडी जाति की लडकी हो और छोटी जाति का लड़का हो, उन की शादी होगी, तभी अन्तर्जातीय विवाह माना जायगा। आज नीची जाति, हरिजन, की लडकी से ऊची जाति के बहुत से लड़के विवाह कर लेते हैं, इसलिये बडी जाति की लडकी और छोटी जाति का लडका विवाह करे तब उस का अन्तर्जातीय विवाह मान कर उन के लिये आइ०ए०एस० और पब्लिक सर्विस कमीशन की सभी जगहो के लिये आरक्षण किया जाय। यदि आप इन सारी चीजो को करते हैं तब इस समस्या का निदान

हो सकेगा। मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि यह देश किसी का नहीं है, चाहे इंदिरा रानी हों, चाहे गांव की महतरानी, दोनों के समान अधिकार हैं।

इस देश में न कोई रहा है और न कोई रहेगा। न राजा रहा है, न रानी रहेगी, यह मिट्टी है, मिट्टी कहानी कहेगी। इसलिये इस पर अमल करने का निश्चय कर के जाइये, जनता पार्टी हरिजनों के लिये काम करे, ताकि आने वाला इतिहास जनता पार्टी को याद करे और भारत सरकार को याद करे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

MR. SPEAKER: Certain amendments to the motion have been moved by some hon. Members. I shall put them to the vote of the House.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura): When the main motion has been withdrawn, there is no need to put these to the vote of the House.

MR. SPEAKER: No, the rules require these to be put to the vote of the House.

Is any hon. Member pressing any particular amendment?

SHRI B. P. MANDAL: I seek leave of the House to withdraw my amendment No. 1.

Amendment No. 1 was, by leave withdrawn.

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa): I seek leave of the House to withdraw my amendment No. 2.

Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn.

SHRI YUVRAJ (Katihar): I seek leave of the House to withdraw my amendment No. 3.

Amendment No. 3 was, by leave, withdrawn.

MR. SPEAKER: Is Shri Rajagopal Naidu there? He is not there. I shall now put amendment No. 4, moved by Shri P. Rajagopal Naidu to the vote of the House.

Amendment No. 4 was put and negatived.

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV (Pratapgarh): I seek leave of the House to withdraw my amendment No. 5.

Amendment No. 5 was, by leave withdrawn.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I seek leave of the House to withdraw my motion.

The motion, was, by leave, withdrawn.

20.10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 10, 1978/Chaitra 20, 1900 (Saka).

GMGIPMRND—I—91 LS(PS)—7-6-78—800.